# गाँधी चिन्तन के आलोक में भारतीय अर्थव्यवस्था : एक विवेचन

* डॉ. श्रीमती संजू गाँधी

एक बार गाँधीजी और गुरुदेव रवीन्द्रनाथ जी के बीच बहस छिड़ गई। ''गुरुदेव ने कहा कि देश के नागरिकों को इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता है कि उनका शोषण भारतीय पुंजीपति कर रहे है या विदेशी पूंजीपति कर रहे है। इस पर गाँधीजी ने उत्तर दिया – स्वदेशी पूंजीपति शोषण करता है तो भी उस शोषण से अर्जित की गई पूंजी से देश में कारखाने लगते है स्वदेशी श्रमिकों को रोजगार मिलता है। गाँधीजी की दृष्टि में देश के पूंजीपति दोस्त थे वे मेंनचेस्टर की कपड़ा मिलों का हित ही नहीं देखते थे।''(1)

गाँधी जी मूलतः अर्थशास्त्री नहीं थे। अतः अर्थव्यवस्था के विकास के संदर्भ में परंपरागत अर्थशास्त्रियों की तरह अर्थशास्त्र के सिद्धातों एवं नियमों के प्रतिपादन में उनकी कोई अभिरूचि नहीं रही, परन्तु सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषयों के बारे में समय –समय पर उन्होनें अपने विचार अभिव्यक्त किये। वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास संदर्भ में उनके आर्थिक दर्शन के स्पष्ट दिशा निर्देश आदर्श बन गए। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में गाँधी जी द्वारा प्रस्तुत किए गये विचार – साम्यवाद, पूंजीवाद, मार्क्सवाद, आदि द्वारा अनुप्रेरित नहीं थे, बल्कि उस त्तकालीन परिवेश में भारत की दीन–हीन दशा एवं प्रथम विश्व युद्ध से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध के बीच दुनिया में घटी नित –नवीन घटनाओं ने गाँधी जी के मन मस्तिष्क पर जो स्पष्ट एवं सीधा प्रभाव डाला था वही अन्तः भारत की सामाजिक – आर्थिक समस्याओं के समाधान स्वरूप उनके मौलिक चिन्तन का आधार बिन्दु बना। यही कारण है कि गाँधी जी का आर्थिक चिन्तन दुनिया की विभिन्न आर्थिक विचार धाराओं से सर्वथा भिन्न एवं अलग प्रतीत होता है। आज भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के विभिन्न अविकसित, अल्पविकसित, एवं विकासशील देशों के लिए गांधी जी का आर्थिक दर्शन एक कल्याणकारी सार्वभौमिक चिन्तन का स्वरूप ले चुका है।

गाँधी जी द्वारा प्रतिपादित निम्नलिखित विचार भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नया जीवन आयाम प्रदान कर सकते हैः– गांधी जी ने सर्वोदय का अर्थ व्यक्ति, समाज, और पूरे राष्ट्र के विकास से लिया है। सर्वोदय अर्थात ''सबका उदय'' अंन्त्योदय अर्थात जो गिरा हुआ है, सर्वप्रथम उसका उदय। उनका विश्वास था कि जब तक विश्व में एक भी व्यक्ति भूखा है, तब तक हमें भर पेट भोजन करने का अधिकार नहीं है। गाँधी जी के सर्वोदय दर्शन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्याय, समानता, एवं बन्धुत्व जैसे आदर्श सम्मिलित है, जिसका उद्देश्य सच्चे प्रजातंत्र को स्थापित करना है। ऐसे सर्वोदय समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए समान अवसर उपलब्ध होगें। निर्धनता, छुआछूत, जात–पात, लिंग–भेद इत्यादि का इसमें कोई स्थान नहीं है। वे ''सर्वधर्म सम्भाव'' के अनुयायी थे। वे आर्थिक समानता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव का ऐसा वातावरण बनाने के पक्ष में थे। जिसमें सभी एक –दूसरे के सहयोगी के रूप में कार्य करें। यही उनके सर्वोदय का मार्ग था।'' पूंजीवाद से उत्पन्न भेदभाव और सामाजिक हिंसा तथा राजकीय पूंजीवाद से उत्पन्न व्यक्तिगत एवं स्वतः प्रेरणा के आस का विकल्प गांधी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है। गाँधी जी का मानना था कि जब तक समाज से आर्थिक विषमता समाप्त नहीं हो जाती, तब तक समाज में स्थायी शांति स्थापित नहीं हो सकती। गाँधी जी सम्पत्ति के अधिकार के उन्मूलन के पक्ष में नहीं थे, किन्तु उनका दृष्टिकोण था कि सम्पत्ति के स्वामियों को सम्पत्ति को समाज की धरोहर समझना चाहिए । उनका विचार था कि भूमि और मकान समस्त समाज के उपयोग के लिए है और इस पर सम्पूर्ण समाज का अधिकार होना चाहिए। धनिकी के पास यदि अधिक धन हो जाता है, तो उसे समाज की धरोहर माने और अतिरिक्त धन का वह ट्रस्टी की भांति समाज हित में प्रयोग करे। देश में धनी और निर्धन वर्ग के बीच की चौड़ी खाई समाज के विकास के लिए हितकर नहीं है। उनका मानना था कि यह खाई धनी वर्ग के लोगों के हितों के लिए भी घातक हो सकती है। साथ ही साथ वह धनी वर्ग की सम्पत्ति को बलात् हथियाने के कतई पक्षधर नहीं थे, इसीलिए ही उन्होनें ट्रस्टीशिप की अवधारणा प्रस्तुत की थी। गाँधी जी भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में आर्थिक समानता की प्राप्ति हेतु विकेन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था के पक्षधर थे। उनका कहना था कि ''मेंरा सुझाव है यदि भारत को अहिंसा के आधार पर अपना नव–निर्माण करना है तो कई क्षेत्रों में विकेन्द्रीकरण का मार्ग अपनाना होगा, अहिंसा का निर्माण आत्मनिर्भर ग्रामों द्वारा ही हो सकता है जैसी की मेंरी धारणा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में शोषण के लिए कोई स्थान नहीं है और शोषण हिंसा का प्रतिरूप है।'' गांधी जी जहां केन्दीयकृत अर्थव्यवस्था के विरोधी थे, वही पंचायती राज एवं आदर्श ग्राम रचना के लिए लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के प्रबल हिमायती भी थे। उत्पादन को छोटे –छोटे पैमानों पर अनेक स्थानों पर चालू किया जाए अर्थात घरों में तथा गाँवों में छोटे –छोटे कुटीर उद्योगों को स्थापित किया जाए। उनके आर्थिक शक्ति के विकेन्द्रीकरण में विश्वास करने का कारण छोटे–छोटे उद्योग धन्धों पर बल देना था। गांधी जी का मानना था कि उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद जैसी बुराइयों की जड़ भी यही केन्द्रीयकृत अर्थव्यवस्था है। गाँधी जी ने भारी उद्योगों के स्थान पर लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना को आवश्यक बताया ।

गाँधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में स्वदेशी पर अधिक बल दिया।गांधी जी के स्वदेशी का अर्थ था विकेन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था, ग्राम और स्थानीय सामुदायिक विकास, सबको रोजगार और स्वावलम्बन ।''(3) इसका अर्थ है स्थानीय आत्मनिर्भरता और सहभागिता । उनके अनुसार शोषणयुक्त वैश्वीकरण का आरम्भ बिन्दु स्वदेशी का अर्थ संकुचित अर्थ में समझते है, परन्तु गाँधी जी के लिए स्वदेशी का अर्थ काफी व्यापक था। उनके अनुसार ''जो करोड़ो भारतीयों के हितों का सम्वर्द्धन करती हो, भले ही उसमें लगी पूंजी व कौशल विदेशी हो, वह स्वदेशी है। गाँधी जी ने कहा कि स्वदेशी की भावना का ने केवल उत्पादन क्षेत्र में बल्कि उपभोग में भी गम्भीरता से पालन किया जाना चाहिए।

गाँधी जी के विचारों की एक सर्वप्रमुख विशेषता यह रही है

* राजनीति विज्ञान विभाग सहायक प्राध्यापक शा. शहीद चन्द्रशेखर आजाद स्नात्तकोत्तर महाविद्यालय

कि वे प्रत्येक समस्या का समाधान सदैव भारतीय परिपेक्ष्य में ही खोजा करते थे, इसी कारण वे भारत जैसे श्रम प्रधान देश में श्रम प्रधान उद्योगों के बदले पूंजी प्रधान वृहत उद्योगों के विकास का विरोध करते थे। गाँधी जी का मानना था कि यन्त्रीकरण उस देश–विदेश के लिए उपयुक्त हो सकता है, जिस देश में श्रम की कमी एवं पूंजी की प्रचुरता हो, भारत जैसे देश में, जहाँ श्रम का आधिक्य एवं पूंजी की न्यूनता है, भारी मशीनों एवं यंत्रो का प्रयोग मानवीय अस्तिव के लिए पूर्णतया अभिशाप है उनका कहना था, कि ''यन्त्रीकरण उस स्थिति में अच्छा सिद्ध होता है। जब काम की मात्रा की अपेक्षा काम करने वालों की संख्या बहुत कम होती है, परन्तु जब काम वालों की संख्या अधिक होती है, जैसा कि भारत में है, तब यन्त्रीकरण एक बुराई होती है। हमारी समस्या यह नहीं है कि गाँवों में रहने वाले करोड़ो मजदूरों और किसानों को किस प्रकार अवकाश प्राप्त होना चाहिए। इसके विपरीत हमारी समस्या उनके खाली अथवा फालतू समय को इस प्रकार उपयोगी बनाने की है कि उन्हें वर्ष में अधिक नहीं तो कम से कम छः मास के लिए कार्य प्राप्त हो सके। उनका कहना था कि मशीनीकरण पर आधारित तीव्र औद्यौगीकरण से मानव का शारीरिक एवं नैतिक पतन हुआ है, और दूसरा मानवीय समाज में आर्थिक सहयोग के स्थान पर आर्थिक असमानता एवं शोषणकारी प्रवृत्तियों में वृद्धि तो जारी है। साथ–साथ भारत जैसे देश में इस यंत्रीकरण एवं मशीनीकरण के कारण गरीबी एवं बेरोजगारी में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, परन्तु यह ध्यान रखने की बात है कि गाँधी जी उन सभी प्रकार की मशीनों के विरोधी थे, जो मानवीय श्रम के महत्व को कम करती हो, एवं सम्पति के केन्द्रीकरण (एकत्रीकरण) को प्रोत्साहित करती हो। वे मानवीय श्रम में बोझ को हल्का करने वाली मशीनों जैसे सिलाई मशीन के हिमायती भी थे। इस प्रकार गांधी जी ने देश में व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी आदि समस्याओं के समाधान के लिए ही मशीनीकरण का विरोध एवं श्रम की महत्ता को स्वीकार किया।

समाज की सारी संपत्ति सारे समाज के सम्मिलित प्रयासों का फल है अतः उस पर सभी व्यक्तियों का समान अधिकार होना चाहिए '' इसलिए वे पूंजीवाद को सामाजिक न्याय का शत्रु मानते थे। उनके लिए समाजवाद का आधार सबके लिए सामाजिक न्याय और अवसर की समानता का सिद्धान्त है। यही उनके सर्वोदयी – समाज की कल्पना का आधार बिन्दु है। गाँधी जी समाजवाद को आर्थिक पुनर्निर्माण का सिद्धान्त मात्र ही नहीं मानते थे, बल्कि उसे सृजनात्मक जीवन दर्शन का एक अंग भी मानते थे।''(4) यह ठीक है कि पश्चिमी देशों में औद्योगिक क्राांति के फलस्वरूप मजदूरों के शोषण में अत्याधिक वृद्धि के कारण ही आधुनिक काल में ''समाजवाद'' को एक आर्थिक राजनीतिक विचारधारा एवं आंदोलन का आयाम मिला। गाँधीजी ने सर्वोत्तम लक्ष्य की प्रगति के लिए श्रेष्ठ साध्य के साथ–साथ पवित्र साधनों को भी स्वीकार करते हुए गाँवों को प्राथमिक इकाई के रूप में माना। उनके अनुसार भारत के पुनर्निर्माण का आधार गांव ही हो सकते है। वे मानते थे कि अगर जनता सुखी एवं सामर्थ्यवान होगी तो उसका राज्य भी शक्तिशाली होगा । गाँधी जी के चिन्तन में गांव भारत के यथार्थ का प्रतीक था, इसलिए उन्होनें गाँवों को राष्ट्रीय पुरूषार्थ का प्रारम्भिक बिन्दु माना, यही कारण था कि गांधी जी एक ''ग्राम केन्द्रित समवित राष्ट्रीय अर्थनीति'' के समर्थक थे।

आय एवं सम्पत्ति के वितरण के संदर्भ में गांधी जी सामाजिक न्याय एवं समानता के सिद्धान्त के पक्षधर थे। उनका कहना था कि प्रत्येक साधन व्यक्ति को आवश्यकता के अनुसार अवश्य प्राप्त होना चाहिए, न कि प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र के प्रत्येक राष्ट्रीय आय में समान भाग। गांधी जी इसी समानता के आधार पर चाहते थे कि एक मनुष्य केवल उतनी सम्पत्ति लेने का अधिकारी है जितना कि उसका पेट भरने के लिए पर्याप्त हो। जो इससे अधिक लेता है वह चोर है। वे आर्थिक एवं सामाजिक विषमता दोनों को देश के लिए एक कोढ़ मानते थे। उन्होनें धन को महत्वपूर्ण मानते हुए भी इसे मात्र केवल एक साधन ही माना।''(5)

गांधी जी श्रम को पूजा मानते थे, उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के परिश्रम द्वारा ईमानदारी से जीविकोपार्जन हेतु प्रयायरत रहना चाहिए। वे पूंजी पर आधारित निर्भरता को समाप्त कर पूंजी निवेश के बदले श्रम निवेश को श्रेयस्कर मानते थे। उनका मानना था कि इससे समाज में समानता आयेगी ओर दूसरे वर्ग – संघर्ष, वर्ग–भेद एवं भुखमरी को दूर करने में सहायता भी मिलेगी। गांधी जी ने देश को सम्पन्न एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपनी आर्थिक नीति को यह आधार प्रदान किया था कि प्रत्येक उपभोक्ता उत्पादक हो और ग्रामोद्योग उसका माध्यम बने। वे श्रम को एक प्राकृतिक नियम मानते थे, और उनका विश्वास था, कि जो व्यक्ति प्राकृतिक नियम का उल्लघंन करता है, वह विपत्ति को आमंत्रित करता है। गांधीजी का मानना था कि श्रम न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मस्तिष्क को भी प्रेरित करता है।''(6)

गाँधी जी का मुल सिद्धान्त था कि देश की पूंजी का उपयोग देश की जनता के हित के लिये किया जाना चाहिये। वे नहीं चाहते थे कि ब्रिटीश पूंजीपति हमारा शोषण करें, गाँधी जी यह भी नहीं चाहते थे कि भारतीय पूंजीपति दूसरे गरीब देशों का शोषण करें। गाँधीजी की दृष्टि में विचारों तकनीकों एवं जानकारी का मुफ्त वैश्वीकरण होना था जिससे हर देश अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपना विकास कर सके। अतः गाँधीजी ने कहा कि में अपने घर की खिड़कियां विदेशी विचारों के लिये खुली रखना चाहता हूं परन्तु घर का दरवाजा बंद रखना चाहता हूं।

इस दृष्टि से वैश्वीकरण का मूल सिद्धांत गरीब देशों को प्रबंधक, उत्पादक, अनुसंधान, आदि की जानकारी सरलता से उपलब्ध करना चाहते थे और गाँधीजी को पूंजी का वैश्वीकरण मंजूर नहीं था क्योंकि उससे शोषण की गंध आती है गाँधीजी के सिद्धान्त के अनुसार भारत में पेटेन्ट कानून के सरलीकरण पर जोर देना चाहिये। गाँधीजी के अनुसार न उसे किसी का शोषण होना चाहिये और न ही किसी का शोषण करना चाहिये।''(7) गाँधी जी की भाषा में शोषण करने को आमंत्रित कर रहे है वे भारतीय कम्पनियों द्वारा दूसरे गरीब देशों के शोषण को भी बढ़ावा दे रहे है। गाँधी जी ने न्याय और धर्म की बात की थी। अपनी कमजोरी से वे विचलित नहीं हुए और उन्होने ब्रिटेन की अन्यायपूर्ण व्यवस्था को चुनौती दी थी।

गाँधी जी का मानना था कि उद्योगवाद वस्तुतः विश्व के अधिकांश जन समाज के स्वतंत्रता का अपहरण करके विश्व जन समाज को मुट्ठी भर लोगों की अधीनता में लाना है। ऐसे विश्ववाद के गाँधी जी घोर विरोधी थे। इसके विपरीत वे ऐसे विश्व के पक्षकार थे जिसमें प्रत्येक समाज को स्वदेशी बुद्धि, स्वदेशी, संस्कृति ,स्वदेशी साधना और स्वदेशी बोली से स्वधर्म का निर्वाह करना है और इस प्रकार विश्व धर्म का एक सहज अंग बनकर रहना है।

यह सत्य है कि परिस्थितियां बदल गई है उस समय देश में परतंत्र था आज देश स्वतंत्र ही नहीं बल्कि आठ फीसदी की दर से विकास भी कर रहा है। विश्व के पटल पर हमारी बहुत अधिक साख है जिसकी वजह से (डब्ल्यूटीओ) वार्ता में हमें प्रमुख स्थान दिया गया। हमें आज गाँधी जी के स्वदेशी सिद्धांत में परिवर्तन करना होगा।

1991 में हमारे देश में जो आर्थिक संकट आया था उसका कारण थी पूंजी और विदेशी विनिमय की कमी। जिसके कारण हमारा विकास अवरूद्ध होने की आशंका पैदा हो गई थी । 1991 के संकट का एक महत्वपूर्ण कारण भी साहूकारी क्षेत्र में फंसी हुई खरबों रूपये की पूंजी थी। उसके हल के रूप में उदारवादी नीति को अपनाया गया। हमारे देश में उदारवादी नीति अपनाये जाने का कारण समाजवादी देशों के अर्थव्यवस्थाओं का पतन भी था जिनसे हमारी अर्थव्यवस्था घनिष्ट रूप से जुड़ी हुई थी। आज भी विकास की दर को बढ़ाने की आवश्यकता पर अधिक बल दिया जा रहा है।

आज राष्ट्र अनेक विभिषिकाओं एवं आर्थिक संकट में फंस चुका है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जो भी प्रयास, नियोजन एवं विनियोग किए जा रहे है, वह सब निरर्थक एवं अर्थहीन होते जा रहे है (वह सब ज्यादा सफल नहीं रहे है) एक ओर जहाँ गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, भुखमरी, जनसंख्या वृद्धि, लिंग असमानता, आय—असमानता आदि मूलभूत आर्थिक — समस्याओं में तीव्र गति से वृद्धि जारी है, वहीं दूसरी तरफ विदेशी ऋणभार, काला धन, व्यापार घाटा, आर्थिक — भ्रष्टाचार आदि समस्याएं भारतीय आर्थिक ढांचे को और अधिक जर्जर करती जा रही है। सम्प्रदायवाद, जातिवाद एवं आतंकवाद ने देश की एकता व अखण्डता को खतरे में डालकर विकास के सम्पूर्ण सुमार्गो को अवरूद्ध कर रखा है। एक और जहां सपन्नता एवं विपन्नता की खाई सिमटने की बजाए और चौड़ी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ राजनैतिक कार्यकुशलता एवं कर्मठता के अभाव में समृद्धिशाली कल्याणकारी योजनाएं असफल होती जा रही है।

समृद्ध एवं शक्तिशाली भारत निर्माण के लिए गाँधी जी के समता वादी समाज की परिकल्पनाओं के अनुसार विकेन्द्रीकरण की आर्थिक नीति एवं पंचायती राज की स्थापना के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण को वास्तविक मूर्त स्वरूप प्रदान किया जाए।''(8)

गाँधी जी द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के तीव्रतर विकास के लिए लगभग पांच दशक पूर्व व्यक्त किए गए उपर्युक्त आर्थिक विचार निःसंदेह आज भी प्रासंगिक है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में अपनी उद्देश्यपरक प्रासंगिकता को सकारात्मक रूप में चरितार्थ करते है। वैसे स्वतन्त्रता के बाद हम 60 वर्ष पार कर चुके है आजादी के बाद हमें कृषि सेवा एवं औद्योगिक प्रगति की एक ठोस एवं वन्दनीय उपलब्धि भी प्राप्त हो चुकी है, लेकिन यह विचित्र किन्तु वास्तविक सत्य है कि देश की दो तिहाई से अधिक निम्न — मध्यमवर्ग की जनता को इस आर्थिक उपलब्धि का तुलनात्मक लाभ नहीं मिला है। ने अपने एक लेख में लिखा है कि ''हमारे आर्थिक विकास के सुनहरे पक्ष कम और धुंधले एवं निराशाजनक पक्ष अधिक है।''(9) नामक सुविख्यात पुस्तक में नोबेल पुरस्कार विजेता का निम्न कथन स्वतः ही सत्यापित हो जाता है कि ''गांधीवाद'' केवल नैतिक आग्रह ही नहीं है, बल्कि एक अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र भी है। जिसमें एक ओर तो आज की आर्थिक जीवन की अनगिनत समस्याओं तथा सामाजिक जीवन में व्याप्त अनेक जटिलताओं का सम्यक सन्निहित है, जो दूसरी ओर सुखद मानवीय भविष्य के लिए स्वतः स्फूर्त क्रांति की दिशा दृष्टि। गाँधी जी के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है, जितने पहले थे।

आज सम्पूर्ण विश्व भयानक आर्थिक मंदी में डुबा हुआ है और भारत भी इसके प्रभाव से अछुता नहीं है। हमारे वैज्ञानिकों, चिंतको अर्थशास्त्रियों को गाँधी जी के स्वदेशी बुद्धि कौशल की नीति को अपनाना होगा। हमारी सभ्यता संस्कृति और मिट्टी से जुड़ा गाँधी जी का चिन्तन एक नये परिष्कृत रूप में अपनाना होगा। गाँधी जी का चिन्तन भारतीय यथार्थ का आईना था उसमें मिलावट की बू नहीं मौलिकता की सुंगध थी। आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था 20 प्रतिशत शहरी कारोबार पर टिकी हुई नहीं है वरन् 80 प्रतिशत ग्रामीण कृषक और मध्यम वर्गीय व्यवस्था पर ही आसीन है। अब हमें गाँधी जी के स्वदेशी अपनाओं के विचार की और मुड़ना होगा। उनका विश्वास था कि भारत के आर्थिक विकास के लिये अनिवार्य है कि उपलब्ध साधनों पर आधारित उत्पादन ईकाइयाँ ही विकसित की जाए और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी देश में उत्पादित वस्तुओं के उपभोग से की जाए। ने कहा कि भारत के सामने वर्तमान में सबसे बड़ी तीन चुनौतियों है — भूख, अशिक्षा और कमजोर जन स्वास्थ्य। भारत इन समस्याओं से निबट रहा है। पिछले कुछ सालों में विकास दर में उच्च स्तर की वृद्धि दिखाई दी है लेकिन गरीबों को इससे कोई विशेष लाभ नहीं मिला है। क्योंकि हमारी योजनाएँ आखरी व्यक्ति तक जा ही नहीं पाती। सरकार को चाहिये की वह गाँधीजी के विचारों को अपनाए, क्रियान्वयन में लाए। हमें भारत की अर्थ व्यवस्था को आधार प्रदान करने, उसे संबल देने के लिए, भारत के स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता की शक्ति को प्राप्त करना है।

**सन्दर्भ ग्रन्थ—**


(1) उदारीरण में गाँधी चिंतन की प्रासंगिकता डॉ. श्रीपाद जोशी, खण्डवा 2002
(2) Gandhi Plan 1944
(3) कुरूक्षेत्र
(4) ग्राम स्वराज्य, हरिप्रसाद व्यास, दिल्ली 2004
(5) Gandhiji Econamic Thoughaaat 1951
(6) मेंरे सपनों का भारत, डॉ. राजेन्द्रप्रसाद अहमदाबाद 2005
(7) गाँधी जी विश्वदृष्टि रामेश्वर मिश्र पंकज दिल्ली 1994
(8) गाँधीजी ने कहा था, डॉ. गिरीराज शरण, दिल्ली 2004
(9) नई दुनिया (समाचार—पत्र)

Hindu Swarajya 1908
Khadi why and Hall 1955
Gandhi Plan 1944
Roat of Econamic Gandhi
अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र डॉ. जी. सी. सिंघई जबलपुर 2004
आत्मकथा एस. के. गाँधी, काशीनाथ त्रिवेदी, अहमदाबाद, 2003
राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी शाहिद प्रहारी, जयपुर 2006
दैनिक भास्कर (समाचार—पत्र)
राज एक्सप्रेस (समाचार—पत्र)
राजस्थान पत्रिका (समाचार—पत्र)